सत्यमेव जयते

राजस्थान शासन

3/13

श्री जगन्नाथ पहाड़िया

मुख्य मंत्री

का

बजट

1981-82

पर

भाषण

शुक्रवार,

6 मार्च, 1981

श्रीमान्

आपकी अनुमति से मैं वर्ष 1981-82 के बजट अनुमान सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं ।

2. अबसे करीब 8 माह पूर्व मैंने इस सदन के सम्मुख इस सरकार का पहला बजट प्रस्तुत किया था । उस समय मैंने माननीय सदस्यों का ध्यान हमें विरासत में मिली राज्य की असन्तुलित अर्थ व्यवस्था की ओर आकृष्ट किया था तथा इसे सही स्थिति में लाने के उपायों से अवगत कराया था । राज्य सरकार के सामने सबसे पहला काम यह था कि वह अपनी कार्य-प्रणाली को संकीर्ण जातिगत तथा साम्प्रदायिक भावनाओं से ऊपर उठाकर, साधनहीन व्यक्तियों का सरकार में विश्वास जाग्रत करें । मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि हमने इस कार्य को सौजन्य एवं दृढ़ संकल्प से पूरा किया है । माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि राज्य की अर्थ व्यवस्था के तेज एवं सन्तुलित विकास के हमारे वचन को पूरा करना, वर्षा के अभाव एवं विद्युत् की कमी तथा अन्य कारणों से कुछ कठिन हो गया । तथापि, इन कठिनाईयों के बावजूद राज्य सरकार अपने इस निश्चय से नहीं डिगी कि समाज की सभी सृजनात्मक एवं उत्पादक शक्तियों को बढ़ावा दिया जाय तथा सार्वजनिक व्यय को अधिकाधिक उत्पादक बनाते हुए, दृढ़ वित्तीय अनुशासन बनाये रखा जाय । जैसाकि मैं कुछ आगे चलकर वर्णन करूंगा, हमने सूखा-पीड़ित जनता की कठिनाईयों को कम करने तथा जन-साधारण के आम उपयोग में आने वाली वस्तुओं को आसानी से सुलभ कराने की कोशिश की है । केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रीमती इन्दिरा गान्धी के योग्य नेतृत्व में उठाये गये कदमों से राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के पुनर्जीवित होने के अच्छे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, जो उज्ज्वल आर्थिक भविष्य का विश्वास दिलाते हैं ।

3. वर्ष 1979-80 के अकाल के पश्चात् पुनः वर्ष 1980-81 में राज्य की अर्थ-व्यवस्था अकाल की छाया से ग्रसित रही। इस वर्ष 26 जिलों में 21,365 गांवों में अकाल की स्थिति घोषित करनी पड़ी। इसके फलस्वरूप व्यापक पैमाने पर राहत कार्यों की व्यवस्था पर व्यय करने के लिये साधन जुटाने पड़े। पेयजल, पशुओं के लिये चारे तथा राहत कार्यों पर रोजगार उपलब्ध कराने में, वर्ष 1980-81 के 27 करोड़ रुपयों के अनुमानित व्यय के मुकाबले अब संशोधित अनुमानों के अनुसार 57.89 करोड़ रुपयों का व्यय अनुमानित है। राज्य सरकार द्वारा सूखा पीड़ित गांवों में खरीफ की भू-राजस्व तथा बारानी जोत वाले व्यक्तियों से पंचायत समितियों की बकाया, सितम्बर, 1981 तक स्थगित करने के आदेश दिये गये। अल्पकालीन सहकारी ऋणों को, मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित किया गया है। फरवरी, 1981 के द्वितीय सप्ताह तक 1,750 सहायता कार्य चालू थे तथा 3 लाख 41 हजार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा था। राज्य सरकार के पास साधनों की कमी है, परन्तु हमने जनता को राहत पहुंचाने में इसे बाधक नहीं बनने दिया है।

4. मानव शक्तियों के नियन्त्रण के बाहर की परिस्थितियों में भी सरकार ने, अपने साधनों एवं संगठन का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति को बनाये रखने में किया जिससे कि समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक उत्थान पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

5. वर्ष 1970-71 के स्थिर मूल्यों पर राज्य का नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्ष 1980-81 में गत वर्ष की तुलना में 1.4 प्रतिशत अधिक है, जो कि इस बात का प्रमाण है कि सूखे की स्थिति की चुनौती का राज्य एवं जनता ने किस दृढ़ प्रयास के साथ मुकाबला किया है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य भी राज्य की जनता, विशेषतः किसानों, खेतिहर मजदूरों तथा अन्य ग्रामीणों के इस धैर्य, निश्चय तथा सहयोग के लिये उनकी सराहना करने में मेरा साथ देंगे।

6. माननीय सदस्यों को विदित है, पिछली सरकार द्वारा रोलिंग योजना अपनाए जाने से योजना प्रक्रिया को कितना आघात पहुंचा था। केन्द्रीय योजना आयोग के नेतृत्व में हमने एक उपयुक्त योजना प्रणाली पुनः स्थापित की है। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने कुछ दिनों पूर्व वर्ष 1980-85 के लिए छठी योजना को अन्तिम रूप दे दिया है। देश की छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अर्थ-व्यवस्था के विकास की गति को और तेज करना है। इसके साथ ही गरीबी और बेरोजगारी में लगातार कमी करना, जन नीतियों द्वारा गरीबों के पक्ष को ध्यान में रखते हुए आय एवं सम्पत्ति असमानताओं में कमी लाना, आमतौर पर जनता के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा विशेषतया समाज के वंचित तबकों को ऊंचा उठाना भी इसका लक्ष्य है। हमारा मानना है कि योजना के प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने में जनता को पूर्ण भागीदार होना आवश्यक है, खासतौर से उन लोगों का जो कि योजना से लाभान्वित होंगे। हमने कुटुम्ब को विकास की एक इकाई के रूप में महत्ता देने पर जोर दिया है। इसका अर्थ यह है कि विभिन्न क्षेत्रों में कुटुम्ब के समूहों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास की योजनाएं बनाई जायं तथा कुटुम्ब के सदस्य स्वयं उन योजनाओं को बनाने में हिस्सा लें। इसके बिना विभिन्न क्षेत्रों में जो क्षमता उपलब्ध है उसका सही विकास नहीं हो सकता। गरीबी दूर करने में कौटुम्बिक दृष्टिकोण अर्थात् हाऊसहोल्ड एप्रोच में परिवार के आर्थिक स्वावलम्बन के साथ-साथ महिलाओं के उद्योग-धन्धे, बच्चों की शिक्षा, छोटे परिवार के माप-दण्ड पर विशेष ध्यान निहित है।

मुझे आपको यह बताते हुए हर्ष होता है कि योजना आयोग द्वारा राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना का आकार 2,025 करोड़ रुपये निश्चित किया गया है जो कि पिछली सरकार द्वारा बनाई गई 1,750 करोड़ रुपये की योजना से 15.71 प्रतिशत अधिक है। राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना में अर्थ-व्यवस्था में औसत वृद्धि

लगभग 5 प्रतिशत होने का अनुमान है। योजना में ऐसे कार्यक्रम रखे गए हैं जिनमें ग्रामीण और दूसरे क्षेत्रों के आर्थिक निर्माण में गति आवे और समाज के कमजोर वर्ग का 25 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार जीवन स्तर ऊंचा उठे और इस प्रकार गरीबी और बेरोजगारी में निरन्तर कमी हो। इससे राज्य आत्म-निर्भर अर्थ-व्यवस्था की ओर अग्रसर होगा। हमारी योजना जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये हमारी नीतियों तथा वादों को दर्शाती है। संक्षेप में छठी योजना में सिंचाई एवं विद्युत् में 1,061.22 करोड़ रुपये (52.41 प्रतिशत), सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं में 386.13 करोड़ रुपये (19.07 प्रतिशत), सिंचाई एवं विद्युत् के अलावा कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं 323.96 करोड़ रुपये (16 प्रतिशत), संचार एवं परिवहन में 136.50 करोड़ रुपये (6.74 प्रतिशत), उद्योग एवं खनिज में 83.59 करोड़ रुपये (4.13 प्रतिशत), सहकारिता में 24.38 करोड़ रुपये (1.20 प्रतिशत) तथा अन्य मदों में 9.22 करोड़ रुपये का विनियोजन प्रस्तावित है।

7. वर्ष 1981-82 की वार्षिक योजना (17 करोड़ रुपये की अग्रिम योजना सहायता सहित) 360.05 करोड़ रुपये की होगी जो कि वर्ष 1980-81 की मूल योजना से 10.78 प्रतिशत अधिक है। वार्षिक योजना में मदवार प्रावधान निम्न प्रकार प्रस्तावित है:–

	(करोड़ रुपयों में)
1. सिंचाई एवं विद्युत्	187.67
2. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	67.33
3. कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	56.38
4. परिवहन एवं संचार	27.45
5. उद्योग एवं खनिज	13.47
6. सहकारिता	4.45
7. अन्य	3.30

8. राज्य की अर्थ-व्यवस्था में ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति राज्य सरकार पूरी तरह सजग है। इस कारण हम विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को उच्चतम प्राथमिकता देते हैं। इस उद्देश्य से वर्ष 1981-82 में ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों पर 511.60 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा 19.51 करोड़ रुपये अधिक है।

9. अब मैं माननीय सदस्यों को कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से अवगत कराना चाहूंगा।

विद्युत्

10. वर्ष 1980-81 में राज्य को विद्युत् की भारी कमी का सामना करना पड़ा जिसका प्रमुख कारण सामान्य से कम वर्षा होना था। इससे सिंचाई परियोजनाओं के जलाशयों के जल-स्तर में कमी आई। साथ ही, राजस्थान परमाणु विद्युत् केन्द्र के बार बार बन्द हो जाने से भी विद्युत् की उपलब्धि में कमी आई। विद्युत् की कटौती के बावजूद, जो इन विषम परिस्थितियों में अनिवार्य थी, हमारा यह प्रयास रहा कि किसानों को यथासंभव नियमित विद्युत् उपलब्ध कराई जाये। माननीय सदस्यों को यह स्मरण होगा कि हमने इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 20 हजार कुओं के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा था। हमें इस बात का संतोष है कि अब तक 19 हजार कुओं का विद्युतीकरण हो चुका है तथा यह आशा है कि 31 मार्च, 1981 तक उपर्युक्त लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। आगामी वर्ष में भी 20 हजार कुओं के विद्युतीकरण का लक्ष्य है।

वर्ष 1981-82 में विद्युत् हेतु 117.12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हमारे प्रयास उत्पादन क्षमता को बढ़ाने तथा उपयुक्त ट्रान्समिशन तथा समुचित वितरण प्रणाली निर्मित करने की दिशा में होंगे जो राज्य की विकासीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। राजस्थान परमाणु-शक्ति केन्द्र की दूसरी इकाई ने प्रायोगिक

आधार पर नवम्बर, 1980 से विद्युत् उत्पादन आरम्भ कर दिया है तथा यह आशा की जाती है कि अतिशीघ्र यह अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन आरम्भ कर देगा। 110 मेगावाट क्षमता वाला कोटा थर्मल (पहला चरण) विद्युत् केन्द्र भी आगामी वर्ष में विद्युत् उत्पादन प्रारम्भ कर देगा। वर्ष 1981-82 से कोटा थर्मल (दूसरा चरण) विद्युत् केन्द्र के लिये 15 करोड़ रुपये, अनूपगढ़ हाइडल योजना के लिये 30 लाख रुपये एवं ट्रान्समिशन व सब-ट्रान्समिशन लाइनों हेतु 40 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इस वर्ष जनवरी, 1981 तक ग्रामीण विद्युतीकरण की 21 योजनायें ग्राम्य विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं। अधिक क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के लिए योजनाएं तैयार करने का काम चालू रहेगा।

सिंचाई

11. राज्य के सिंचित कृषि के क्षेत्रफल को और अधिक बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना बनाते समय अधूरी योजनाओं को पूरा करने के कार्य को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। इसके पश्चात् आधुनिकरण के कार्य को तथा जन-जाति क्षेत्र एवं मरुस्थल के अविकसित जिलों में नई योजनाएं प्रारम्भ करने को प्राथमिकता दी गई है। राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के लिये 393.47 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें से वर्ष 1981-82 की वार्षिक योजना पर 67.00 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

राजस्थान नहर के निर्माण के लिये अगले वर्ष 25 करोड़ रुपये का प्रावधान है। माननीय सदस्य यह जानते हैं कि कोयला तथा सीमेन्ट की कमी से इस नहर के तीव्र गति से निर्माण में बाधा आई है। मैंने व्यक्तिगत रूप से इस परियोजना के लिये अधिकतम कोयले तथा सीमेन्ट की आपूर्ति प्राप्त करने की कोशिश की है तथा भविष्य में भी मैं इस पहलू पर नजर रखूंगा। इन दोनों वस्तुओं की उपलब्धि के आधार पर यदि आवश्यक हुआ तो वर्ष में और अधिक प्रावधान उपलब्ध कराया जायेगा।

सिंचाई से अधिकतम लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से पुरानी सिंचाई प्रणालियों के आधुनिकरण की निरन्तर मांग रही है जो उचित भी है। सिंचाई प्रणालियों के आधुनिकरण के लिये छठी पंचवर्षीय योजना में 35.00 करोड़ रुपये हैं जिसमें से वर्ष 1981-82 के लिये 4.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें गंग नहर तथा भाखरा प्रणाली के तथा कुछ मध्यम परियोजनाओं के आधुनिकरण की व्यवस्था है। ऐसी आशा है कि वर्ष 1981-82 में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं से 20 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। वर्ष 1980-85 में जो अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी वह दो लाख हेक्टेयर है।

जन-जाति क्षेत्र विकास

12. माननीय सदस्य जन-जाति के उत्थान के लिये राज्य सरकार के प्रयासों से अवगत है। वर्ष 1981-82 में लगभग 45 करोड़ रुपये राज्य योजना मद में, 3.80 करोड़ रुपये विशेष केन्द्रीय सहायता में तथा 2.98 करोड़ रुपये केन्द्र प्रवर्तित योजना में जन जातियों के विकास के लिये उपलब्ध होंगे। संस्थागत वित्त से भी 2.38 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे।

राजस्थान लघु उद्योग निगम के माध्यम से चल रहे 13 प्रशिक्षण केन्द्रों में से 5 प्रशिक्षण केन्द्र अगले वर्ष से प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र में परिवर्तित किये जावेंगे। इससे आदिवासियों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इस वर्ष 580 व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिलाया गया। आदिवासी क्षेत्र में टी. बी. के इलाज के लिये विशेष अनुदान की व्यवस्था की जा रही है। क्षय रोग से बीमार आदिवासियों को अपने घर से चिकित्सा केन्द्र तक

जाने आने एवं दवाइयों तथा पौष्टिक आहार की सुविधा उपलब्ध होगी। कुओं को ब्लास्टिंग द्वारा गहरा कराने के लिये शत प्रतिशत अनुदान दिये जाने के कार्यक्रम को अधिक गतिशील बनाया जावेगा। आशा है कि लगभग 1,500 कुओं को ब्लास्टिंग द्वारा गहरा किया जावेगा। 5 लघु स्वास्थ्य केन्द्र एवं 3 नये आश्रम स्कूल भी प्रारम्भ किये जावेंगे। एक लाख आदिवासी छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क पौशाक एवं पुस्तकें वितरित की जावेंगी तथा 23 छात्र व 23 छात्राओं को प्रतिभावान छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जावेगी। कड़ाना बांध के बैंक वाटर में मत्स्य आखेट योजना प्रारम्भ की जावेगी जिससे आदिवासी परिवारों को आर्थिक लाभ मिल सकेगा।

आदिवासियों को मुफ्त कानूनी सहायता दिलाये जाने सम्बन्धी नियमों का राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है। इससे आदिवासियों को गैर-आदिवासियों के विरुद्ध दीवानी एवं राजस्व मुकदमों में 250 रुपये तक की अधिकतम सहायता उपलब्ध हो सकेगी।

इस वर्ष सहकारी आधार पर आदिवासियों को अधिक सहकारी ऋण उपलब्ध कराये गये तथा आर्थिक गतिविधियों में विभिन्न स्रोतों से सहायता दिलाई गई। अगले वर्ष इन गतिविधियों को और अधिक सुदृढ़ एवं विकसित किया जावेगा।

समाज कल्याण

13. योजना विनियोजन के अधिकतम लाभ दिये जाने हेतु अनुसूचित जातियों, जन-जातियों, वर्गीकृत जातियों, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जन-जाति के व्यक्तियों के विकास की दृष्टि से उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, पारिवारिक तथा घरेलू कार्यक्रमों के जरिये विकास करने पर जोर होगा। इस वर्ष की उल्लेखनीय उपलब्धि अनुसूचित जातियों के लिये कम्पोनेन्ट प्लान का निर्माण है, जिसका उद्देश्य उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है। इस वर्ष इसमें करीब 40.45 करोड़ रुपये का व्यय, विभिन्न कार्यक्रमों पर होगा जिससे एक लाख से अधिक परिवारों को लाभ पहुंचेगा। अगले वर्ष करीब इतनी ही राशि अनुसूचित जाति के कल्याण के लिये प्रावधित है। राज्य के बाकी तीन जिले यथा-झुंझुनूं, बूंदी तथा झालावाड़ में अगले वर्ष समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालय खोले जायेंगे।

मरु क्षेत्र

14. माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि 13 जिलों में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रमों तथा मरु विकास कार्यक्रमों को लागू किया गया है जिनका उद्देश्य सूखे की स्थिति की गम्भीरता को तथा कृषि की मानसून पर निर्भरता कम करना है। यह कार्यक्रम जिनमें अगले वर्ष 20 करोड़ रुपये के लगभग व्यय होंगे और अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाता रहेगा। अन्य सामान्य योजनाओं के अतिरिक्त अगले वर्ष 39.54 लाख रुपये का प्रावधान मरु उद्यान विकास के लिये रखा गया है। 30 नये पशु चिकित्सालय भी खोले जाएंगे तथा वनों के क्षेत्र में भी बहुत बड़े पैमाने पर कार्यक्रम हाथ में लिये जाएंगे।

औद्योगिक एवं खनिज विकास

15. छठी योजना में हमारा प्रयत्न यह होगा कि द्रुत औद्योगिक विकास के लिये सभी उपलब्ध क्षमताओं का उपयोग किया जाय। इस वर्ष इस सम्बन्ध में किये गये प्रयत्नों का बहुत अच्छा परिणाम आया है। वर्ष 1980-81 में 43 आशय-पत्र, 10 औद्योगिक लाइसेन्स तथा 26 टैक्सटाइल इकाइयों की राजस्थान में स्थापना के लिये परमिट भारत सरकार द्वारा दिये गये। 5 आशय-पत्र सीमेन्ट कारखाने लगाने के लिये दिये गये। अशोक लेलैण्ड राज्य में ट्रक चैसीज बनाने के लिये एक फैक्टरी की स्थापना करेगा। इसके लिये

करार पर हस्ताक्षर हो चुके हैं तथा भूमि भी आवंटित की जा चुकी है।

राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम द्वारा इस वर्ष दिसम्बर, 1980 तक 4.72 करोड़ रुपये के सावधि ऋण दिये गये जो कि अब तक की उपलब्धियों में अधिकतम हैं। अगले वर्ष यह निगम 15 करोड़ रुपये के सावधि ऋण देगा जिससे करीब 160 करोड़ रुपये का विनियोजन होने की आशा है। करीब 790 एकड़ जमीन उद्योगों की स्थापना के लिये विकसित की जाएगी। राज्य की 1981-82 की वार्षिक योजना में इस निगम के लिये 4.50 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

राजस्थान वित्त निगम ने इस वर्ष दिसम्बर, 1980 तक 28.33 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये हैं जिससे 1828 उद्यमियों को लाभ पहुंचा है। निगम ने विशेष शर्तों पर अनुसूचित जातियों के उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए भी एक योजना बनाई है। वर्ष 1981-82 में निगम द्वारा 32 करोड़ रुपये के ऋण वितरण का लक्ष्य है, इसमें से 3 करोड़ रुपये के ऋण वितरण का लक्ष्य अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिये निर्धारित किया गया है। राज्य की वार्षिक योजना में इस निगम के लिये 92 लाख रुपये का प्रावधान है।

इस वर्ष 13,492 अस्थायी इकाइयां तथा 4,153 स्थायी इकाइयां पंजीकृत हुई, जिनमें लगभग 26 करोड़ रुपये का विनियोजन हुआ जिसकी 20 हजार व्यक्तियों को रोजगार देने की क्षमता है। वर्ष 1981-82 के लिये 12 हजार दो सौ औद्योगिक इकाइयों के पंजीकरण का लक्ष्य है। एक ग्रामीण औद्योगिकरण ब्यूरो की स्थापना का भी प्रावधान है। जिला औद्योगिक केन्द्र दस्तकारों तथा लघुतम इकाइयों को पचास लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराएंगे।

वर्ष 1981-82 में खादी के उत्पादन का लक्ष्य 18.25 करोड़ रुपये के मूल्य का है। खादी उद्योग में रोजगार प्राप्त कर रहे व्यक्तियों की संख्या 1 लाख 45 हजार से बढ़कर 1 लाख 52 हजार हो जाने की संभावना है। ग्रामोद्योग में वर्ष 1981-82 में 12 हजार अतिरिक्त कामगारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, जिससे ग्रामोद्योगों में रोजगार प्राप्त कर रहे व्यक्तियों की संख्या 78 हजार से बढ़कर एक लाख हो जाएगी।

राज्य के क्षेत्रीय विकास में असन्तुलन को दूर करने की दृष्टि से जन-जाति क्षेत्रों में औद्योगिकरण के कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आगामी वर्ष सिरोही जिले में लगभग 7 करोड़ रुपये की लागत से एक सिन्थेटिक्स कारखाना स्थापित किया जा रहा है जिससे लगभग 700 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा। राजस्थान वित्त निगम ने भी वर्ष 1980-81 में जनवरी, 1981 तक 355.72 लाख रुपये के ऋण आदिवासी बाहुल्य जिलों में स्वीकृत किये हैं तथा 240.82 लाख रुपये का ऋण वितरण भी किया जा चुका है। इन जिलों में पिछले वर्ष की अपेक्षा ऋण स्वीकृत करने एवं ऋण वितरण दोनों में ही गति आई है।

खनिज क्षेत्र में राज्य सरकार का प्रयत्न राज्य की खनिज सम्पदा की खोज की तरफ रहा है। इस समय 33 ऐसी परियोजनायें हाथ में हैं। इस वर्ष नागौर जिले में मेड़ता रोड़ के पास तथा बाड़मेर जिले में कपूरडी में लिगनाइट का पता चला है। खान विभाग की अगले वर्ष की योजना में 2 करोड़ रुपये का प्रावधान उनकी गतिविधियों को तेज करने के लिये किया जा रहा है। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम को भी 50 लाख रुपये उपलब्ध कराये जाएंगे। निगम यह आशा करता है कि माण्डव की पाल में फ्लोराइट बैनीफिसियेशन प्लान्ट तथा बाड़मेर में बेन्टोनाइट क्रसिंग प्लान्ट अगले वर्ष उत्पादन आरम्भ कर देगा। सिरोही जिले में मल्टी-मैटल के जो भण्डार उपलब्ध हुए हैं, उनके नमूनों की जांच हिन्दुस्तान जिंक

लिमिटेड द्वारा की जा रही है तथा उसके सहयोग से प्रारम्भिक प्रतिवेदन भी तैयार किया जा रहा है। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम के लिये अगले वर्ष 80 लाख रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। निगम यह आशा करता है कि अगले वर्ष बैनीफिसियेशन पायलट प्लान्ट चालू हो जाएगा, जिससे निगम हल्की ग्रेड के रॉक-फास्फेट के पूर्ण उपयोग का कार्यक्रम बना सकेगा।

कृषि

16. हमारी अर्थ-व्यवस्था अब भी मुख्य रूप से कृषि पर ही निर्भर है। छठी योजना में कृषि विकास में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने पर बल दिया गया है। तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जावेगा जिससे कि वर्ष 1981-82 में 6.8 लाख टन उत्पादन होगा जो कि चालू वर्ष के संभावित उत्पादन से 74.36 प्रतिशत अधिक होगा। 2.03 लाख क्विन्टल उन्नत बीज तथा 2.80 लाख टन उर्वरकों का अगले वर्ष वितरण करने का लक्ष्य है जो वर्ष 1980-81 की तुलना में 70 से 100 प्रतिशत अधिक होगा। किसानों को फलदार वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जावेगा। इसके लिए 15 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त पौधे दिये जायेंगे।

सरकार का प्रायोगिक आधार पर फसल बीमा योजना प्रारंभ करने का विचार है एवं इसकी रूपरेखा बनाई जा रही है।

सहकारिता

17. छठी योजना का उद्देश्य प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों को सुदृढ़ बहुद्देशीय इकाइयों में विकसित करना है जिससे कि किसानों, दस्तकारों तथा खुद के निजी धन्धे वाले व्यक्तियों को एक ही केन्द्र पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो जावें। 1984-85 के अन्त तक 90 प्रतिशत किसानों को सहकारिता के क्षेत्र में लाने का लक्ष्य है। 30 जून, 1980 को समाप्त होने वाले सहकारी वर्ष में किसानों को विभिन्न अवधि के करीब 100 करोड़ रुपये के ऋणों का वितरण किया गया। वर्ष 1981-82 में इसे बढ़ा कर 139 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य है। इस वर्ष परिपूर्ण ऋण योजना प्रारम्भ की गई, जिसमें प्रत्येक जिले में 2 ग्रामीण सेवा सहकारी समितियों का चयन किया जाकर उनके परिवारों की आर्थिक आवश्यकताओं का सर्वेक्षण कर आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत 550 परिवारों को 10 लाख रुपये के ऋण दिये जा चुके हैं। इस योजना का और अधिक विस्तार किया जाएगा। सहकारी समितियों हेतु अगले वर्ष 788 गोदामों का निर्माण युरोपियन इकोनामिक कमेटी की सहायता से चल रहे कार्यक्रम में किया जाएगा।

एकीकृत ग्राम विकास

18. जैसाकि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं, समाज के कमजोर वर्गों को ऊंचा उठाने के लिये हाउस-होल्ड अप्रोच अर्थात् कौटुम्बिक दृष्टिकोण को महत्ता दी गई है। एकीकृत ग्राम विकास योजना इसी उद्देश्य की पूर्ति करती है। इस वर्ष में करीब 41 हजार ग्रामीण परिवारों को दिसम्बर, 1980 तक लाभ पहुंचाया गया है, जिसमें 18 हजार से अधिक परिवार अनुसूचित जाति/जन जाति के हैं। इसी प्रकार 6,260 ग्रामीण युवकों द्वारा अपना प्रशिक्षण लाभकारी स्वयं नियोजन की दृष्टि से पूर्ण कर लिया जाएगा। अगले वर्ष की योजना में इस कार्यक्रम के लिये 6 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिससे करीब 1.40 लाख परिवारों को लाभ पहुंचेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन तथा अधिक आधारभूत सुविधायें उपलब्ध हो सकेंगी।

डेयरी विकास

19. डेयरी विकास कार्यक्रमों में इस वर्ष निरन्तर प्रगति हुई

है। यद्यपि इस वर्ष हमारा लक्ष्य 4 लाख लीटर प्रतिदिन औसत दुग्ध संकलन का था परन्तु अकाल की स्थिति के कारण यह सम्भव नहीं हो सका। अगले वर्ष पुन: हमारा लक्ष्य 4 लाख लीटर प्रतिदिन औसत संकलन का है। डेयरी सहकारी समितियों की सदस्यता, जो कि 1980-81 में 1.12 लाख थी, वह 1981-82 में 1.50 लाख होने की आशा है। 1.5 लाख लीटर क्षमता की डेयरी अगले वर्ष जयपुर में कार्य प्रारंभ कर देगी। अगले वर्ष राज्य में 5 अवशीतन केन्द्र स्थापित करने का कार्य आरंभ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक डेयरी का कार्य भी हाथ में लिया जाएगा। हम श्वेत क्रान्ति का स्वप्न साकार करने की दिशा में सतत् प्रयत्नशील हैं।

वन विकास

20. छठी योजना में सामाजिक वन योजना पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे ग्रामों की बेकार भूमि तथा सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण किये जाएंगे, नहरों तथा सड़कों आदि के किनारे वृक्षारोपण क्षेत्र बनाए जाएंगे तथा डिग्रेडेड वनों का सुधार किया जाएगा। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 में वनों के विकास पर 12.63 करोड़ रुपये व्यय होंगे। विकास की यह योजना मरुस्थल जिले, जन जाति जिले तथा राजस्थान नहर परियोजना सहित राज्य के सभी क्षेत्रों में क्रियान्वित की जाएंगी।

शिक्षा, कला और संस्कृति

21. शिक्षा के क्षेत्र में छठी योजना का प्रमुख लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा को और अधिक सुदृढ़ एवं सुलभ कराना है। इसमें अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के तथा ऐसे वर्गों के बालक-बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष जोर होगा, जो कि अपनी विशेष परिस्थितियों के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं। 6 से 14 वर्ष के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में वार्षिक वृद्धि की गति हमें बहुत अधिक बढ़ानी पड़ेगी। मैं इस अवसर पर माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे सर्व-सुलभ प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य को कम से कम समय में प्राप्त करने के लिये अपना सक्रिय सहयोग दें।

शिक्षा पर 153.75 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है, जो कि इस वर्ष की अपेक्षा 16.44 करोड़ रुपये अधिक है। वर्ष 1981-82 में 400 नये प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे तथा 100 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा। प्राथमिक विद्यालयों की चतुर्थ कक्षा की सभी छात्राओं के लिये उपस्थिति प्रोत्साहन योजना को लागू किया जायेगा जो अब तक केवल तीसरी कक्षा तक लागू है। कुछ माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त खण्ड तथा विषय शुरू किये जायेंगे। कुछ महाविद्यालयों में भी अतिरिक्त विषय खोले जायेंगे।

वर्ष 1981-82 में जयपुर में सार्वजनिक पुस्तकालय के लिये 25 लाख रुपये की लागत के भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा। जयपुर में इण्डोर स्टेडियम के निर्माण हेतु वर्ष 1981-82 में 10 लाख रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। रविन्द्र मंच, जयपुर में ओपन एयर थियेटर के निर्माण के लिये 3 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

माननीय सदस्यों को मुझे यह बताते हुए हर्ष होता है कि केन्द्रीय सरकार ने सिद्धान्त रूप से जयपुर में हिन्दुस्तानी संगीत का केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने केन्द्र की स्थापना हेतु एक लाख रुपये का प्रावधान रखा है।

वर्ष 1981-82 में राज्य में संस्कृत अकादमी की स्थापना भी की जा रही है, जिसके लिये आवश्यक प्रावधान किया जा रहा है।

चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य

22. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसके ढांचे के असन्तुलन को छठी योजना में दूर करने पर जोर होगा जिससे कि

ग्रामीण क्षेत्रों तथा गरीब वर्गों के लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। वर्ष 1981-82 की वार्षिक योजना में इसके लिये 9.01 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जो कि गत वर्ष की तुलना में लगभग 22 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 1981-82 में राज्य में 35 नई डिस्पेन्सरी और 15 एड-पोस्ट खोलने का प्रस्ताव है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं को उपयुक्त रूप से सशक्त बनाया जायेगा।

जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर तथा उदयपुर के मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध अस्पतालों में दुर्घटना तथा आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे कि वरिष्ठ एवं प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी 24 घन्टे वहां उपलब्ध हो सकें। जयपुर में 16 अतिरिक्त काटेज वार्डों का भी निर्माण किया जाएगा। यू. एन. एफ. पी. ए. (यूनाइटेड नेशन्स फण्ड फोर पोपुलेशन एक्टीविटीज) योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं का एक सघन कार्यक्रम कोटा, भरतपुर तथा सवाई माधोपुर जिले में चल रहा है। आधुनिक तरीकों से 500 दाइयों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि उनकी सेवाएं दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हो सके। अगले वर्ष इस परियोजना पर 336.74 लाख रुपये का प्रावधान किया जा रहा है, जो कि इस वर्ष की तुलना में तीन गुणा अधिक है।

राज्य सरकार जनसंख्या की वृद्धि को नियन्त्रित करने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सतत् प्रयत्नशील रहेगी। इस वर्ष फरवरी तक 89,000 नसबन्दियां की गई। हमारा यह लक्ष्य है कि अगले वर्ष और अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिये जनता को विश्वास में लेकर सघन रूप से प्रयत्न किये जायं। मुझे विश्वास है इस कार्य में माननीय सदस्यों का सहयोग उपलब्ध होगा।

आवासन एवं नगरीय विकास

23. अगले वर्ष की योजना में इस मद में 5.83 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है, जिसमें 75 लाख रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भू-खण्डों के विकास एवं गृह निर्माण पर व्यय किये जायेंगे तथा 1.20 करोड़ रुपये राजस्थान आवासन मण्डल को उपलब्ध कराये जायेंगे। ऐसी आशा है कि अगले वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कमजोर वर्ग के 10 हजार परिवारों को इससे लाभ पहुंचेगा तथा राजस्थान आवासन मण्डल शहरों तथा कस्बों में 10 हजार मकान उपलब्ध करा सकेगा। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विभिन्न योजनाओं में 20 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है। 6 शहरों में पर्यावरण सुधार कार्यक्रम के लिये 40 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

सिंचित क्षेत्र विकास

24. राजस्थान नहर तथा चम्बल क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र कार्यक्रम प्रगति पर है तथा इसके लिये अगले वर्ष की योजना में 12.15 करोड़ रुपये का प्रावधान है। राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में 30 किलोमीटर लम्बी नहरों को पक्का किया जायेगा तथा 38 हजार 4 सौ हेक्टेयर क्षेत्र में पानी के मोगों को पक्का किया जायेगा। चम्बल क्षेत्र में इस वर्ष 8,500 हेक्टेयर भूमि में बाराबन्दी की गई है तथा यह आशा की जाती है कि अगले वर्ष 25 हजार हेक्टेयर भूमि में बाराबन्दी प्रणाली लागू हो जाएगी।

शरणार्थियों का पुनर्वास

25. मुझे यह बताते हुए हर्ष होता है कि 1971 के भारत-पाक युद्ध के समय आये हुए 3 हजार शरणार्थी-परिवारों को राजस्थान नहर क्षेत्र में बसाने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है। भारत सरकार इस कार्य के लिये 9 करोड़ रुपये ऋण एवं अग्रिम के रूप में देगी। पुनर्वास के कार्य में होने वाले दूसरे व्यय की पूर्ति के

लिये भी वह ऋण देगी और ऐसी आशा है कि पुनर्वास का यह कार्य अगले वर्ष पूरा हो जायेगा ।

जल-प्रदाय

26. माननीय सदस्यों को यह विदित है कि इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक हमने 2 हजार और गांवों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। अप्रेल, 1980 से जनवरी, 1981 तक राज्य सरकार यह सुविधा 1816 और गांवों में उपलब्ध करा चुकी है। हमें आशा है लक्ष्य पूरा प्राप्त कर लिया जायेगा। अब कुल मिलाकर 6,675 गांवों में यह सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। हमारी योजना है कि पेयजल की कठिनाई वाले सभी गांवों में 4 वर्षों में इस समस्या का समाधान हो जाए। अतः वर्ष 1981-82 में 2700 गांवों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। पेयजल के लिये अगले वर्ष कुल मिलाकर 31.31 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में साधनों की कमी आड़े नहीं आने दी जावेगी।

सड़कें

27. राज्य में 1971 की जनगणना के अनुसार 5 हजार से अधिक आबादी वाले सभी गांव मार्च, 1981 तक सड़कों से जुड़ जाएंगे। 4 हजार से 5 हजार की आबादी के बीच वाले 26 गांवों को जोड़ने वाली सड़कों के कार्य भी प्रारंभ किये जा चुके हैं। इस वर्ष 1500 से अधिक आबादी वाले 95 और गांवों तक सड़कों की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। वर्ष 1981-82 में 16.25 करोड़ रुपये का प्रावधान सड़कों एवं पुलों के निर्माण के लिये किया जा रहा है। हमें आशा है कि लगभग 1000 किलोमीटर और कुल नई सड़कों का निर्माण संभव हो सकेगा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा राज्य पथ पर माही नदी पर पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अगले वर्ष बांसवाड़ा रतलाम सड़क पर माही नदी के पुल का कार्य पूर्ण हो जाने पर यह क्षेत्र मध्य प्रदेश से भी जुड़ जावेगा।

राज्य सरकार सड़क परिवहन द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु दुर्घटना बीमा योजना अगले वर्ष आरंभ करेगी जिससे क्षतिग्रस्त व्यक्ति को समुचित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

पर्यटन

28. पर्यटकों के लिये राजस्थान आकर्षण का केन्द्र रहा है। प्रति वर्ष राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस वर्ष करीब 2 लाख विदेशी तथा 24.5 लाख भारतीय पर्यटकों ने दिसम्बर, 1980 तक राजस्थान का भ्रमण किया है। राजस्थान पर्यटक विकास निगम द्वारा कई पर्यटन-उत्सवों का विभिन्न लोकप्रिय स्थानों पर आयोजन किया गया, जिसके उत्साहवर्धक परिणाम निकले। हमारा यह प्रयत्न होगा कि ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएं जो राजस्थान की संस्कृति और कला के विभिन्न पक्षों को प्रदर्शित कर सकें तथा भविष्य में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित कर सके। अगले वर्ष 4 नये पर्यटक सूचना-केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त राजस्थान ट्यूरिस्ट डवलपमेन्ट कारपोरेशन के माध्यम से इसमें प्रगति का प्रयास किया जायेगा। राज्य सरकार भारतीय पर्यटन विकास निगम को राज्य में अपना विनियोजन और कार्यकलापों में वृद्धि करने हेतु निवेदन करेगी।

संस्थागत वित्त

29. विकास शील अर्थ-व्यवस्था में व्यक्ति पर आधारित विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने में वित्तीय संस्थाओं को महत्वपूर्ण योग अदा करना है। हमारा प्रयत्न यह है कि बैंकों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जाय तथा उनसे अधिकतम वित्तीय सहायता उपलब्ध हो। राज्य सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से 193 और

केन्द्रों पर व्यवसायिक बैंकों की शाखायें खोलने हेतु आग्रह किया है। आशा है कि जून, 1981 तक इन केन्द्रों पर शाखायें खुल जाएंगी। राज्य सरकार यह प्रयत्न करेगी कि राज्य में विभिन्न सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं को तथा व्यक्तियों को अधिकाधिक संस्थागत वित्त उपलब्ध हो।

30 राज्य सरकार द्वारा विभिन्न राजकीय निगमों/बोर्डों इत्यादि में बहुत अधिक पूंजी विनियोजन किया हुआ है। राज्य सरकार यह अपेक्षा करती है कि उसे इस पूंजी विनियोजन में अपेक्षित लाभ मिलना चाहिये। वर्ष 1981-82 में हमारा प्रयत्न होगा कि जो निगम/बोर्ड घाटे की स्थिति में है वे अपनी व्यवस्था इस प्रकार करें कि अब और अधिक घाटा न हो। साथ ही वे पूंजी निवेश पर न्यूनतम लाभ भी राज्य सरकार को दें। इस दृष्टि से यदि आवश्यक हो तो वे अपने मूल्यों, सेवा की दरों, लागत दरों पर पुर्नविचार करें। मैं यह अपेक्षा करता हूं कि यह सभी निगम/बोर्ड इस स्थिति को समझेंगे तथा अपनी कार्य-प्रणाली की आवश्यक समीक्षा करेंगे।

कर्मचारी कल्याण

31. राज्य कर्मचारियों को 1 सितम्बर, 1980 से महंगाई भत्ते की एक और किस्त देय हो गई है। यद्यपि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति महंगाई भत्ते की इस देय किस्त को चुकाने की स्थिति में नहीं है फिर भी राज्य कर्मचारियों के प्रति सद्भाव की दृष्टि से राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि इसका भुगतान 1 सितम्बर, 1980 से नकद कर दिया जाय। इससे 1300) रु. तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 8) रु. से 30) रु. तक का प्रतिमाह लाभ होगा। इससे राज्य कोष पर वर्ष 1981-82 में 10.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को भी 1 सितम्बर, 1980 से पेन्शन राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इससे सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को 5) रु. से 15) रु. प्रतिमाह तक का लाभ होगा। इससे राज्य कोष पर वर्ष 1981-82 में 1.20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

मद्य-निषेध

32. राज्य में 1 अप्रेल, 1980 से पूर्ण मद्य-निषेध लागू है परन्तु इस बीच अवैध शराब के बनाने और उसके उपयोग की शिकायतें आती रही हैं। अतः मद्य-निषेध नीति के विवेकीकरण हेतु उपाय सोचे जायेंगे।

संशोधित अनुमान 1980-81

33. वर्ष 1980-81 के संशोधित अनुमानों की समग्र स्थिति इस प्रकार है :–

	(करोड़ रुपये में)
1. राजस्व प्राप्तियां	730.30
2. राजस्व व्यय	686.99
3. राजस्व खाते में बचत	+43.31
4. पूंजीगत प्राप्तियां	343.92
5. योग (3+4)	387.23
6. पूंजीगत व्यय	414.76
7. शुद्ध घाटा (6–5)	–27.53

माननीय सदस्यों को यह ज्ञात होगा कि वर्ष 1980-81 के परिवर्तित बजट में 58.04 करोड़ रुपये की घाटे की स्थिति दिखाई गई है। उसमें 30.51 करोड़ रुपये की कमी होकर अब 27.53 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा संशोधित अनुमानों के अनुसार रहने की संभावना है।

बजट अनुमान 1981-82

34. वर्ष 1981-82 के बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

	(करोड़ रुपयों में)
1. राजस्व प्राप्तियां	721.50
2. राजस्व व्यय	692.76
3. राजस्व खाते में बचत	+28.74
4. पूंजीगत प्राप्तियां	296.46
5. योग (3+4)	325.20
6. पूंजीगत व्यय	355.61
7. शुद्ध घाटा (6–5)	–30.41

महंगाई भत्ते एवं पेंशन में वृद्धि के कारण वर्ष का घाटा 11.70 करोड़ रुपये और बढ़ जायेगा जिससे वर्ष 1981-82 में कुल घाटा 42.11 करोड़ रुपये हो जायेगा।

वर्ष 1980-81 के संशोधित अनुमानों की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 1981-82 में यद्यपि 8.80 करोड़ रुपये की कमी दृष्टिगोचर होती है परन्तु इसका कारण केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न ऋणों के अपलेखन के कारण प्राप्त होने वाले संभावित अनुदान को संशोधित अनुमानों में सम्मिलित किया जाना है। यदि इस राशि को कम करके वर्ष 1981-82 की राजस्व प्राप्तियों की तुलना की जावे तो 36.38 करोड रुपये की वृद्धि दृष्टिगत होगी। राजस्व व्यय में संशोधित अनुमानों की तुलना में 5.77 करोड़ रुपये मात्र की वृद्धि है।

35. राज्य के सर्वांगीण विकास के लिये साधनों की व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक है। विकास की गति को हम अवरुद्ध नहीं कर सकते तथा यह भी संभव नहीं है कि साधनों एवं व्यय के अन्तर की यह स्थिति और अधिक समय तक चलती रहे। अतः अतिरिक्त साधनों की व्यवस्था करना आवश्यक है। इसके बावजूद में फिलहाल कोई अतिरिक्त करारोपण प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं तथापि निम्नलिखित करों में रियायत के प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं :–

(1) पिछले वर्ष नेत्रहीनों की मदद के लिये कुछ वस्तुओं को बिक्री कर से मुक्त किया था। अब यह प्रस्ताव है कि ब्रेल कागज तथा ब्रेल घड़ियों को भी बिक्री कर से मुक्त कर दिया जावे।

(2) यंत्रीकरण के इस युग में यंत्रों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। इससे जीवन यापन भी महंगा होता जा रहा है और जन-साधारण के स्वास्थ्य और ग्रामीण जीवन की आत्म-निर्भरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः हाथ से चलने वाली पत्थर की चक्की को कर मुक्त कर दिया जावे, इससे आत्मनिर्भरता एवं पौष्टिक आहार के स्रोत बनाये रखने में सहायक होगा और ऐसे परिवारों को थोड़ी सी आर्थिक राहत भी मिल सकेगी।

(3) साधनहीन व्यक्तियों के लिये ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में लकड़ी की हाथ गाड़ी रोजगार का साधन है। अतः लकड़ी की हाथ गाड़ी एवं उसके लकड़ी के सभी उपकरण बिक्री कर से मुक्त करने का प्रस्ताव है।

36. वर्ष 1979-80 के अन्त में महालेखाकार के आंकड़ों के अनुसार 25.93 करोड़ रुपये का घाटा था। वर्ष 1980-81 के अन्त में संशोधित अनुमानों के अनुसार 27.53 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है। अतः वर्ष 1981-82 का प्रारम्भ 53.46 करोड़ रुपये की घाटे की स्थिति से होने का अनुमान है। इसे वर्ष 1981-82 के घाटे में जोड़ने के पश्चात् वर्ष 1981-82 के अन्त में कुल घाटा

95.57 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इसकी पूर्ति राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि खण्डों के विक्रय को अधिक गतिशील बनाकर, शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तन करने से होने वाली आय, बकाया राजस्व की वसूली एवं केन्द्रीय सरकार से मिलने वाले करों के अंश में संभावित वृद्धि से पूरा किया जायेगा।

37. श्रीमान्, मैंने सदन को आगे आने वाले वर्षों में राज्य के विकास की प्रस्तावित दिशा से अवगत कराया है। कांग्रेस सरकार ने राज्य के विकास की नींव रखी थी और हम जिन्हें कि राज्य की जनता की सेवा करने का सौभाग्य मिला है, राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए वचनबद्ध हैं एवं इस ध्येय की प्राप्ति के लिये पूरी शक्ति से कार्य करेंगे। यद्यपि साधनों की कमी दृष्टिगोचर होती है परन्तु फिर भी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी द्वारा दिये गये 20 सूत्रीय कार्यक्रम को पूरा करने के लिये हम तत्परता की भावना से कार्य करने में अग्रसर होंगे। मैं राजस्थान के सर्वांगीण विकास के कठिन कार्य में योगदान करने के लिये इस सदन के सभी माननीय सदस्यों तथा समाज के सभी वर्गों का आह्वान करता हूं।

38. श्रीमान्, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वर्ष 1981-82 के बजट अनुमान सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं।

जयहिन्द !